THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Efforts of the Geological Survey of India (GSI) have brought to light at present only small isloated deposits which cannot be commercially exploited.

Closure of charge chrome Industries in Orissa

1154. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the pitiable condition of Asia's largest charge Chrome industries in Orissa due to closure of a major charge chrome plant, rendering hundreds of employees jobless, as reported in the Economic Times, New Delhi, dated 22nd November, 1993;

(b) whether such a closure has been due to the unequitable distribution of the mining leases aggravating the user industries;

(c) what steps have been taken or are proposed to be taken to intervene and solve the issue of mining lease; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on Table of the House.

Deregulation of Mineral Processing Industry

1155. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided or contemplate to deregulate mineral processing industry to allow private sector to explore new areas with or without foreign equity participation;

(b) if so, the details thereof, indicating, benefits, the States will be deriving from it and to what extent and in which type of mines these will be allowed; and

(c) the details of proposals received or cleared so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Private sector participation in all mineral processing industries have already been permitted, as per the statement on Industrial Policy, 1991.

(b) and (c) Do not arise.

देश में सोने का वार्षिक उत्पादन

1156. **श्री अजीत जोगी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर सोने की खानें स्थित हैं;

(ख) देश में सोने का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या सरकार को इन खानों के प्रचालन से घाटा हो रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) प्रत्येक राज्य और विशेषतः मध्य प्रदेश में सोने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कराये जा रहे सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देश में सोने

की प्रचलित खानें निम्न स्थानों पर हैं:-

कम्पनी/खान	स्थान
खान का नाम	
I. भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	
(1) मैसूर चैम्पियन एकीकृत खान	कोलार गोल्ड फील्ड क्षेत्र, कोलार जिला कर्नाटक
(2) नन्दीदुर्ग खान	-वही-
(3) येप्पामाना खान	अनन्तपुर जिला, आंध्र प्रदेश
(4) चिगारमुंटा खान	चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश
(5) पुरानी बिसनाथम खान	-वही-
II. हट्टी गोल्ड माइंस कम्पनी लिमिटेड	
(1) हट्टी गोल्ड माइंस	रायचूर जिला, कर्नाटक

(ख) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान देश में सोने का उत्पादन क्रमशः 2090 कि०ग्रा०, 2036 कि०ग्रा० और 1837 कि०ग्रा० हुआ।

(ग) और (घ) भारत गोल्ड माइंस लि० को अयस्क भंडारों के समाप्त होने, अयस्क ग्रेड में गिरावट आने और कम्पनी में अधिशेष कर्मचारी होने आदि कारणों से घाटा हो रहा है।

(ङ) मध्य प्रदेश में दो गवेषणों सहित, देश में स्वर्ण अयस्कों हेतु 41 स्थानों पर गवेषण कार्य किये गये हैं। फील्ड सत्र 1993-94 में किये गये गवेषण कार्यों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है :

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	खनिज गवेषण निगम लिमिटेड
कर्नाटक-9	कर्नाटक-1
आंध्र प्रदेश-7	आंध्र प्रदेश-2
केरल-3	केरल-1
राजस्थान-3	
मध्य प्रदेश-2	
महाराष्ट्र-2	
तमिलनाडु-2	
बिहार-2	
उड़ीसा-2	
उत्तर प्रदेश-2	
पश्चिम बंगाल-1	
हरियाणा-1	
पंजाब-हिमाचल प्रदेश-1	

मध्य प्रदेश के रायगढ़ और बस्तर जिलों में अब तक की गई खोजों से निम्न स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है, इसलिये क्षेत्र में ड्रिलिंग का कार्य रोक दिया गया है।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बालको) के सलाहकारों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति

1157. **श्री अजीत जोगी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भर्ती नीति के विरुद्ध भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बालको) में इस कम्पनी से सेवा निवृत्त कई अधिकारियों की नियुक्ति सलाहकारों के रूप में की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन सलाहकारों के नाम क्या हैं और इन पर गत दो वर्षों के दौरान कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) इस अतिरिक्त खर्च में कमी करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?